भारतीय मौद्रिक प्रणाली (Indian Monetary Policy)

भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागजी मुद्रा मान कहा जाता है, कागजी करेंसी का भारत में प्रामाणिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में कागजी करेंसी के साथ धातविक सिक्के भी चलन में होते हैं, भारत में सिक्के सीमित विधि ग्राह्य तथा कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य हैं।

भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था :- भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को 'न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था' कहते हैं।

(i) सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा न्यूनतम (₹ 115 करोड़) होती है तथा प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ 85 करोड़ होता है। अतः कुल सुरक्षित कोष का मूल्य केवल (₹ 115 करोड़ + ₹ 85 करोड़) = ₹ 200 करोड़ है।

(ii) लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वह सब साख मुद्रा ही होती है इसे जारी करने वाली संस्था इस मुद्रा को सोने या चाँदी में परिवर्तित नहीं कर सकती।

(14)

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money) :- मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय किसी एक समय बिंदु पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। देश की सरकार तथा समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास पड़ी मुद्रा को मुद्रा के स्टॉक का भाग नहीं माना जाता है।

मुद्रा की पूर्ति के माप :- मुद्रा की पूर्ति के चार वैकल्पिक माप हैं m_1, m_2, m_3 और m_4।

m_1 माप :- m_1 = जनता के पास करेंसी + माँग जमाएं + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं

या $m_1 = C + DD + OD$

m_2 माप → इसमें m_1 के सभी घटकों के अतिरिक्त डाकखानों में लोगों की बचतों को भी शामिल किया जाता है।

अतः m_2 = m_1 + डाकखानों के बचत खातों में जमाएं

m_3 माप :- इसमें m_1 के सभी घटकों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है।

अतः m_3 = m_1 + व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं।

m_4 माप :- इसमें m_3 के सभी घटकों के अतिरिक्त डाकखानों की जमाओं को सम्मिलित किया जाता है।

अतः m_4 = m_3 + डाकखानों की कुल जमाएं (NSC को छोड़कर)

भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? :- भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय एक रुपए के नोट जारी करता है तथा सिक्के ढालता है। मुद्रा जारी करने का कार्य मुख्य रूप से केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) करता है। RBI न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। रिजर्व बैंक को ₹ २०० करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखनी पड़ती हैं। व्यापारिक बैंक माँग जमा के आधार पर साख उत्पन्न मुद्रा पूर्ति का निर्माण करते हैं। जब व्यापारिक बैंक लोगों को साख प्रदान करते हैं तो इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वे साख का संकुचन करते हैं तो मुद्रा की पूर्ति कम होती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार ही व्यापारिक बैंकों को मुद्रा की पूर्ति का विस्तार या संकुचन करना पड़ता है।

मुद्रा की आदर्श पूर्ति :- देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी वह मुद्रा की आदर्श पूर्ति कहलाएगी। इस पूर्ति के फलस्वरूप देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना संभव होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेंगी तथा मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम है तो कीमतें कम हो जाएँगी, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तथा देश में बेरोजगारी फैल जाएगी। अतः देश के केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति के उचित स्तर को बनाए रखना है।